विचार बिन्दु

उपदेश के बजाय कहीं ज्यादा हम करके सीखते हैं। –बर्क

समाचार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं!

"समाचार पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है", यह कथन प्रथम दृष्टया अजीब, अतिरंजित या विडंबनापूर्ण लग सकता है, किंतु जब हम आधुनिक मीडिया की प्रकृति, प्रस्तुति शैली और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं, तो इस कथन में एक गहन यथार्थ छिपा पाते हैं। आज का मीडिया दिन-भर सनसनीखेज, नकारात्मक, भय पैदा करने वाली और उत्तेजक खबरों से भरा रहता है। युद्ध, राजनीतिक घृणा, घोटाले, आपदाएं, हत्या, बलात्कार आदि खबरों के रोज़मर्रा के विषय हो गए हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि लगातार ऐसी नकारात्मक सूचनाएं पढ़ना और देखना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह चिंता, अवसाद, क्रोध, और अनावश्यक भय को जन्म देता है। कई अध्ययन यह दर्शाते हैं कि नकारात्मक खबरों की अधिकता लोगों में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त, समाचारों का सतहीपन और पक्षपातपूर्ण प्रस्तुति भी एक बड़ी चिंता है। समाचारों में तथ्यों की गहराई कम होती जा रही है, और विचारधारात्मक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। इससे पाठक भ्रमित होता है, उसकी निष्पक्ष सोच कमजोर होती है, और समाज में कटुता व असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में खबरें सच्चाई बताने के बजाय विचार थोपने का माध्यम बन कर ज्ञान के बजाय तनाव का कारण बन जाती हैं।

मीडिया की नई 'ब्रेकिंग न्यूज़' संस्कृति ने सूचना को इतना क्षिणक और अधीर बना दिया है कि ध्यान केंद्रित करने की लोगों की क्षमता कम होती जा रही है। हर क्षण कुछ नया जानने की लालसा एक किस्म की 'सूचना लत' (इनफॉर्मेशन एडिक्शन) पैदा कर रही है, जो मानसिक थकान और असंतोष को बढ़ाने का कारण बन रही है। हालांकि यह कहना कि 'समाचार पढ़ना हानिकारक है' अतिशयोक्ति हो सकता है, फिर भी यह कथन हमें चेतावनी अवश्य देता है कि हमें समाचारों के उपयोग के तरीके और मात्रा को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि हम गुणवत्ता पूर्ण, संतुलित और विश्लेषणात्मक समाचार स्त्रोतों को चुनें; खबरों को आत्मसात करने से पहले संदर्भ को समझें; और दिन भर की हर नकारात्मक घटना को अपनी मानसिक शांति पर हावी न होने दें। वास्तव में इस कथन में एक गहरी सीख छिपी है कि समाचार पढ़ो, लेकिन सोच-समझकर, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की नुकसानदायक हो सकती है – सूचना की भी। बाज़ार ने डिजिटलीकरण के जरिए सीधे-सादे समाचारों को मनोरंजन व्यवसाय का हिस्सा बना कर उसे सामूहिक विनाश के एक हथियार में बदल दिया है, जो सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निशाना साध रहा है।

विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे दूर हटने में ही हमारा भला है। हमारा समाचारों के उपभोग को सीमित करना कोई त्याग करना नहीं है। सही मायनों में हमें इसका भरपूर फायदा मिलेगा। हमें ज़्यादा समय मिलेगा, नई नज़र मिलेगी, और वह चीज मिलेगी जो वास्तव में मायने रखती है – वह चीज है खुशी।

समाचार हमारे जीवन का वैसा ही हिस्सा रहा है जैसा आंख खुलने पर सुबह की चाय। सुबह-सुबह लोग चाय हाथ में लिये सामने अखबार फैला कर उसे ऐसे पढ़ते है जैसे कोई पंडित व्यास पीठ पर बैठ रामायण या गीता का पाठ कर रहा हो। अब लोग आंख खुलते ही अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाये ऐसे डूबे रहते हैं जैसे दुनिया का संचालन उन्हें ही करना हो। 1990 के दशक में इंटरनेट के आगमन के साथ, जानने के लिए अचानक और भी बहुत कुछ हो गया। अचानक सब कुछ सामने आ गया। दुनिया के हर कोने से समाचार आने लगे व्यापक, तत्काल और सभी मुफ़्त। ऐसे में डिजिटल तकनीक से मुनाफा कमाने वाले हमें खबरें लगातार जानते रहने की लत लगा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, जिसकी हमें खबर ही नहीं होती। कहते हैं कि खबरें शराब से भी अधिक खतरनाक होती हैं, क्योंकि शराब पीने की राह में आने वाली बाधाओं को पार करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि सोशल मीडिया ने खबरों की राह अत्यंत आसान कर दी है। सटीक शब्दों में कहें तो, शराब पीने से रोकने के लिये सामाजिक, चिकित्सकीय और वैधानिक व्यवस्थाओं की बाधाएं हैं, जबकि इसके उलट हमें खबरें पढ़ने के लिए तो सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, लुभाया जाता है।

कहते हैं कि खबरें शराब से भी अधिक खतरनाक होती हैं, क्योंकि शराब पीने की राह में आने वाली बाधाओं को पार करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि सोशल मीडिया ने खबरों की राह अत्यंत आसान कर दी है। सटीक शब्दों में कहें तो, शराब पीने से रोकने के लिये सामाजिक, चिकित्सकीय और वैधानिक व्यवस्थाओं की बाधाएं हैं, जबकि इसके उलट हमें खबरें पढ़ने के लिए तो सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, लुभाया जाता है।

शराब खरीदने के लिये मेहनत लगती है, समय लगता है और पैसा लगता है। शराब हमारे घर पर मुफ़्त में नहीं पहुंचाई जाती है। अगर किसी को शराब की लत लग जाती है तो हमारे दोस्त, रिश्तेदार उसे छुड़ाने के उपाय करते हैं। साथी लोग लत लगे शराबी से बोतलें छिपाते हैं। शराब सच में एक झंझट हो जाती है। मगर खबरें शराब जैसी झंझट नहीं पैदा करती हैं।

खबरें हर जगह उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात कि वे ज़्यादातर मुफ़्त मिलती हैं। मगर वे हमारे दिमाग में नशे की तरह घर कर जाती हैं। शराब की बोतलों की तरह हमें खबरों को कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में उन्हें निपटाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। क्योंकि खबरें लुभाती हैं और उन्हें चलाने वाले उन्हें लोगों के अवचेतन में टांग देना चाहते हैं, इसीलिए इनके उत्पादक उन्हें कपटी बनाते हैं। जब तक किसी को इसका एहसास होता है जब तब तक वह खबरों को देखने में हज़ारों घंटे बिता चुका होता है। थोड़े समय पहले अनुसंधानकर्ताओं ने खबरों में हमेशा सिर घुसाये रहने वालों से दो सवाल पूछे थे:– क्या अब आप दुनिया को बेहतर समझते हैं? और क्या आप बेहतर फैसले लेते हैं? दोनों ही मामलों में अनुसंधानकर्ताओं को जवाब 'नहीं' में मिला। फिर भी लोग खबरों की इस भारी-भरकम, भड़कीली दुनिया की तरफ लगातार खिंचे चले जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से बेचैन करने वाली स्थिति है। समाचार रिपोर्टों के छोटे-छोटे टुकड़े लोगों की वास्तविकता में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने लंबे पाठों को एक साथ पढ़ना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोगों के ध्यान को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। मगर आम लोगों में किसी को यह घबराहट नहीं होती कि वे अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कभी वापस नहीं पा सकेंगे। वे इन टुकड़ों को फिर कभी एक पूरे में नहीं समेट पाएंगे।

समझदारी इसी में है कि खुद को खबरों के रंगमंच से धीरे-धीरे अलग करना शुरू कर दिया जाए। अपने स्मार्टफोन से न्यूज़लेटर्स और आरएसएस फ़ीड हटा दिए जाएं और खुद को केवल कुछ वेबसाइटों तक सीमित रखने की कोशिश की जाए। किन्तु यह अत्यंत मुश्किल काम है, क्योंकि एक लिंक से दूसरी लिंक पर झूलते रहना हमारी नियति हो चली है और हम सभी खबरों के अंतहीन जंगल में तेज़ी से भटकते जा रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें एक क्रांतिकारी समाधान की ज़रूरत है, और अभी ज़रूरत है। इसलिए जितना जल्दी हो यह फैसला कर लिया जाए कि अब और कोई खबर नहीं। पूर्ण विराम। यह फैसला यदि कठोरता से लागू किया जाए तो वह तत्काल कारगर साबित हो सकता है। मगर खुद को खबरों की लत से आज़ाद करने में समय, इच्छाशक्ति और प्रयोग करने की तत्परता की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बढ़कर, इन सवालों के जवाब तलाश किए जाने चाहिए कि खबर क्या है? वह क्या चीज है जो इसे इतना लुभावना बनाती है? किसी खबर को पढ़ते हुए या देखते समय हमारे दिमाग में क्या होता है? खबरें हमें इतनी जानकारियां देती है फिर भी हम क्योंकर इतना कम जानते हैं? खबरों को इतनी गंभीरता से त्यागना किसी के लिये भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि खबरों का आभासी संसार सर्वत्र पसरा पड़ा हैं। फिर मीडियकर्मी हैं जो अपने को सबसे बुद्धिमान और परिष्कृत लोगों में से मानते हैं और अधकचरी जानकारी देना अपना अधिकार समझते हैं। उन्हें घमंड है कि उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए यह पेशा मुख्यतः नैतिक आधार पर चुना है। किन्तु दुर्भाग्य से, अब वे एक ऐसे उद्योग में फंस गये हैं जिसका वास्तविक पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं है।

खबरों के इस सारे जोड़-तोड़ और प्रपंच ने उनके काम को निरर्थक बना दिया है। कुछ सुधि लोग मानते है कि समाचारों के मोह और उनकी लत से मुक्त होकर पूरा 'क्लीन' हुआ जा सकता है। समाचारों से मुक्त ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो इस आज़ादी के प्रभावों को देख और महसूस कर रहे हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से बता भी सकते हैं। वे बताते हैं कि खबरों के प्रपंच वाले जाल से बाहर निकलने से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, सोच अधिक स्पष्ट होती है, और मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। इन सबसे ऊपर हमें बहुत अधिक समय मिल सकता है। ऐसा कहने वालों ने अपने अखबारों की सदस्यता रद्द कर दी है, टीवी समाचार देखना बंद कर दिया है, रेडियो बुलेटिनों से ध्यान हटा लिया है और खुद को ऑनलाइन समाचारों के संपर्क में आने से रोक दिया है। किसी का एक व्यक्तिगत प्रयोग के रूप में शुरू किया गया यह अभ्यास उनके लिये जीवन दर्शन जैसा बन गया है। लत छुड़ाने के लिये कहा जा रहा है कि 'समाचार स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है' तो वह स्पष्ट विवेक के साथ कहा जा रहा है। ऐसा जीवन को बेहतर बनाने के लिये कहा जा रहा है। इस यकीन के साथ कहा जा रहा है कि इस लत को त्यागने से कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं खो जाएगी।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा,
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

एग्रीटेक हब बनने की ओर अग्रसर राजस्थान

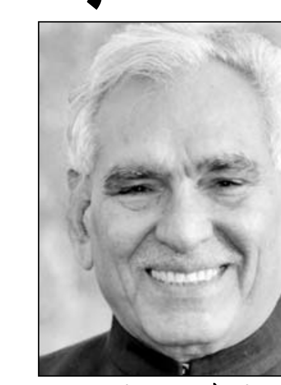

सी. आर. चौधरी

चुनौतियों को अवसरों में बदलना आधुनिक राजस्थान की पहचान बन चुका है। एक समय था जब मरुस्थलीय भू-भाग, सीमित जल संसाधन और कठोर जलवायु यहां की कृषि के सामने बड़ी बाधा माने जाते थे। किंतु आज वही राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में 'कृषि नवाचार' का अग्रणी केंद्र बनकर उभर रहा है। तकनीक, निवेश और किसान कल्याण के सशक्त त्रिकोण पर आधारित नीतियों ने कृषि को लाभकारी बनाया है और इसे राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन भी बना दिया है। आगामी 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026' इस दिशा में राजस्थान को वैश्विक कृषि मानचित्र पर स्थापित करने की क्षमता रखता है।

परंपरागत रूप से राजस्थान को कृषि की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य माना जाता रहा है। यहां की 60 प्रतिशत से अधिक भूमि शुष्क या अर्ध-शुष्क श्रेणी में आती है और औसत वर्षा भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। जल संकट और बार-बार आने वाले सूखे ने किसानों की आय और उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक प्रभावित किया। लेकिन बीते वर्षों में दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग और निवेश-आधारित दृष्टिकोण ने इस परिदृश्य को बदल दिया है। आज राजस्थान देश के कृषि मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ अग्रणी राज्य है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कृषि को केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए जयपुर में 23 से 25 मई तक 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026' का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कृषि क्षेत्र में नवाचार, निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और वैश्विक सहयोग का एक बड़ा मंच बनेगा। इसमें देश-विदेश के वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, उद्योगपति और किसान एक साथ जुटकर खेती के भविष्य की दिशा तय करेंगे। किसानों को आधुनिक तकनीकों-जैसे प्रिसिजन फार्मिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खेती और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त किसान, समृद्ध भारत के विजन को राजस्थान सरकार प्रभावी रूप से लागू कर रही है। राज्य का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने के साथ ही कृषि को वैल्यू चेन से जोड़कर उसे लाभकारी बनाना है। इसके तहत फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और एग्री-एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजस्थान की कृषि विविधता और उत्पादन क्षमता इसे देश में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। राज्य आज बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और सरसों, ग्वार और जौ के उत्पादन में भी अग्रणी है। मसालों में जीरा, धनिया और ईसबगोल जैसे उत्पादों में राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय पहचान है। औषधीय और जैविक खेती के क्षेत्र में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार इन उत्पादों के लिए स्पाइस पार्क, एग्री-प्रोसेसिंग क्लस्टर और निर्यात केंद्र विकसित कर रही है। 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' में कृषि क्षेत्र को लेकर निवेशकों की अभूतपूर्व रुचि देखने को मिली। इस समिट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग 44 हजार करोड़ रुपये के 2,500 से अधिक एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इनमें से करीब 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। यह निवेश न केवल कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के साथ ही लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा।

राज्य सरकार कृषि में तकनीकी हस्तक्षेप को प्राथमिकता दे रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देकर जल संरक्षण को सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक लगभग 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हजारों डिग्गियों और पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से जल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले दो वर्षों में 65 हजार से अधिक सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम हुई है और सिंचाई अधिक सुलभ बनी है। सौर ऊर्जा आधारित खेती लागत को के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन को भी राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के तहत पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जबकि मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स के माध्यम से गांव-गांव में पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' के अंतर्गत पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है।

राज्य सरकार की नीतियों के केंद्र में किसान है। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष करना, फसल बीमा योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये के दावों का भुगतान, गेहूं पर बोनस और 'गोपाल क्रेडिट कार्ड' जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देकर किसानों को बाजार से सीधा जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। डिजिटल कृषि भी राजस्थान की नई पहचान बनती जा रही है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा रहा है। ड्रोन तकनीक के जरिए फसल की निगरानी, उर्वरक छिड़काव और उत्पादन अनुमान को अधिक सटीक बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से खेती को स्मार्ट और लाभकारी बनाया जा रहा है।

'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026' इन सभी प्रयासों का समेकित स्वरूप प्रस्तुत करेगा। यह आयोजन निवेशकों को आकर्षित करने, तकनीकी सहयोग बढ़ाने और किसानों को वैश्विक कृषि से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। इससे राजस्थान न केवल देश में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक अग्रणी एग्रीटेक हब के रूप में स्थापित हो सकेगा।

–सी. आर. चौधरी,
अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग

भेदभावपूर्ण और गलत नीतियों से दलहन के किसान 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से वंचित

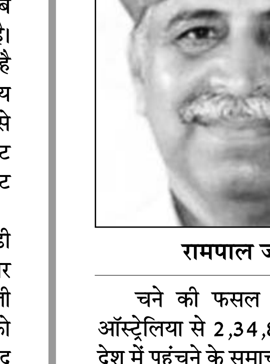

रामपाल जाट

चने की फसल आने के पूर्व ऑस्ट्रेलिया से 2,34,800 टन चना देश में पहुंचने के समाचार हैं। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है। बाजार भाव 4,800 से लेकर 5,200 रूपये प्रति क्विंटल है। सरकार की खरीद प्रभावी नहीं रहती है, खरीद का प्रबंधन ढीला-ढाला रहता है। किसानों की आय के संरक्षण के नाम पर राज्यो के कुल उत्पादन में से 75 प्रतिशत उत्पादन को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर धकेला हुआ है। किसानों की रक्षार्थ भारत सरकार ने छत्रक योजना के रूप में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान वर्ष 2018 से आरंभ किया हुआ है, इस योजना की उद्देशिका में तिलहनों के साथ दलहन उपजों को भी लाभकारी मूल्य दिलाने का उल्लेख है। इसी योजना की मार्गदर्शिका में कुल उत्पादन में से 25 प्रतिशत से अधिक की खरीद को प्रतिबंधित किया हुआ है। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 में यह प्रतिबंध आरोपित किया गया था। 25 प्रतिशत से अधिक खरीद के लिए भारत के कृषि मंत्रालय को छूट देने का अधिकार रखा गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद इस प्रतिबंध को हटाने की अपेक्षा थी। प्रतिबंध को हटाया तो नहीं गया बल्कि 25 प्रतिशत से अधिक खरीद की छूट देने का प्रावधान कृषि मंत्रालय के साथ वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालय को भी जोड़कर कठोर बना दिया गया। दूसरी ओर लूट रहित दाने-दाने की खरीद करने के किसानों के आग्रह को ठोकर मार दी गई। किसानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए 31 अगस्त 2022 को मसूर, अरहर एवं उड़द की खरीद के प्रतिबंध में 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया। उसी क्रम में 1 अप्रैल 2024 से इन तीनों दलहनों की खरीद के प्रतिबंध को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। किंतु मूंग एवं चना में यह प्रतिबंध यथावत चल रहा है। इस भेदभाव का कारण अरहर, मसूर एवं उड़द आयात की तुलना में चने एवं मूंग की मात्रा कम हो जाना बताया। किसी विद्यार्थी के अपेक्षाकृत अधिक अंक आ जावे तो उसे पुरस्कृत करने के स्थान पर दंडित करने जैसी यह कार्यवाही है। किसानों के निरंतर आंदोलन करने के उपरांत चने की शत-प्रतिशत खरीद में 25 प्रतिशत का प्रतिबंध बाधा बना हुआ है।

4 सितंबर 2025 को दालों में आत्मनिर्भरता पर नीति आयोग के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के उपरांत आरंभ किया है। किंतु वह भी किसानों को चने का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिला पा रहा है। चना उत्पादन में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। अपवादों को छोड़कर चना की खरीद किसी भी वर्ष में प्रतिबंधित सीमा से अधिक नहीं हुई। वर्ष 2020-21 में चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,200 रुपए प्रति क्विंटल होते हुए भी किसानों को एक क्विंटल पर 1,000 रुपए तक का घाटा उठाकर बेचना पड़ा था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राजस्थान में जयपुर जिले के उपखंड दूदू क्षेत्र में 500 से अधिक चने से लदे हुए ट्रैक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सप्ताह से अधिक समय तक आंदोलित रहे थे। इस अवधि में अन्नत्याग सत्याग्रह से भी सरकारों का दिल नहीं पसीजा था। यह तो नेफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने उनके गोदाम में जमा लगभग 15 लाख टन चने की खुली बिक्री किसानों के आठाह पर रोक दी थी, जिससे बाजार में चने के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो गए थे, तब आंदोलनरत किसानों को उनके चने का घोषित न्यूनतम दाम प्राप्त होना संभव हुआ था।

वर्ष 2025-26 में चने की सी-2 संपूर्ण लागत 4,875 रुपए प्रति क्विंटल है, भारत सरकार की ओर से बजट 2018-19 में लागत से डेढ़ गुना दाम निर्धारण की घोषणा के अनुसार एक क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,312.50 रूपये होना चाहिए था, किंतु भारत सरकार ने एक क्विंटल के लिए 5,875 रूपये की घोषणा की है। जबकि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' का निर्धारण डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय किसान आयोग' (2004-2006) की अनुशंसा के अनुसार व्यापक लागत में 50 प्रतिशत लाभांश जोडकर निर्धारण किया जाना चाहिए। मूल्य निर्धारण के बाद खरीद में सरकारी ढुल- मुल व्यवहार का परिणाम भी किसानों को भोगना पड़ता है, यथा-खरीद नीति का

केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद राज्यों द्वारा अधिसूचना प्रसारित करने में 41 दिन तथा राज्यों द्वारा प्रसारित अधिसूचना के उपरांत वास्तविक खरीद में 73 दिन तक का विलंब इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकारों की भेदभावपूर्ण गलत नीतियों एवं ढिलाई के कारण किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी वंचित रहना पड़ता है। चने पर जून 2006 से लेकर दिसंबर 2017 तक आयात शुल्क शून्य था, उसके बाद 30 प्रतिशत, फरवरी 2018 में 40 प्रतिशत, मार्च 2018 में 60 प्रतिशत था, जिसे घटाकर फरवरी 2021 में 10 प्रतिशत ₹ 50 प्रतिशत अतिरिक्त कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर, 4 मई 2024 से 31 मार्च 2025 तक शून्य कर दिया गया, 1 अप्रैल 2025 से 10 प्रतिशत है। पीली मटर के आयात के लिए 4 मई 2024 से 31 मार्च 2026 तक आयात शुल्क शून्य कर दिया गया। वर्ष 2015-16 में चने के आयात की मात्रा 10.3 लाख टन थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 16.1 लाख टन हो गई। इससे आयात पर खर्च की गई राशि 4,454 करोड़ से बढ़कर 10,307 करोड रुपए हो गई। भारत सरकार द्वारा चने के आयात पर आरोपित 60 प्रतिशत शुल्क को घटाकर शून्य तक लाने का भी दुष्परिणाम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। देश में चने का क्षेत्रफल 2020-21 में 107 लाख हेक्टर से घटकर 2024-25 में 96 लाख हेक्टर रह गया। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के लगभग बराबर रहे, मार्च 2021 से मार्च 2024 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहे। वर्ष 2023-24 में चने की खरीद कुल उत्पादन में से मध्य प्रदेश में 25.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 24.3 प्रतिशत, गुजरात में 25.3 प्रतिशत तथा राजस्थान में 13.7 प्रतिशत रही। वर्ष 2022 -23, 2023 -24 2024- 25 की 3 वर्षों की अवधि में देश के कुल उत्पादन में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की भागीदारी दो तिहाई से अधिक है, जो क्रमश 26.2 प्रतिशत, 24.4 प्रतिशत, 16.5 प्रतिशत है। गुजरात की भागीदारी 11.1 प्रतिशत को सम्मिलित करने पर इन चारों राज्यों की भागीदारी ही 78.2 प्रतिशत है। संयोग से देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, जो चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री राजस्थान में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से हैं, जो चना उत्पादन में राजस्थान में अग्रिम पंक्ति में है, इसी क्षेत्र की विधानसभा दूदू से निर्वाचित विधायक उपमुख्यमंत्री हैं। मूंग उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके उपरांत भी प्रतिबंध के कारण चना एवं मूंग के 75 प्रतिशत उत्पादक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल घोषित था। प्राकृतिक आपदा के कारण मूंग की लगभग आधी पैदावार चौपट हुई। आपूर्ति कम तथा मांग अधिक होने पर मूल्य में बढ़ोतरी होती है, इस सिद्धांत के विपरीत किसानों को एक क्विंटल मूंग घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 3000 रुपए से अधिक का घाटा उठाकर बेचना पड़ा। सरकार ने अनेक बार संसद में किसी भी किसान को उसकी उपज घोषित 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होने के प्रति आश्वस्त किया हुआ है।

किसानों ने भी खेती करने का अर्थ उत्पादन की गतिविधियों तक मान लिया है। जबकि इसमें दाम प्राप्त करना भी सम्मिलित है। लाभ में संतोष करना उत्तम गुण है, किंतु लाभ प्राप्ति के लिए क्रियाशील नहीं रहना कमजोरी है। 'संतोषी सदा सुखी' जैसी कहावत को आधार बनाकर सामर्थ्य प्रकट करने से बचने के लिए कम दाम प्राप्त होने को अपना भाग्य समझ लिया है। जैसे-कोई चालणी लेकर दूध निकालने के लिए दुधारू पशु के नीचे बैठ जाए फिर घर तक दूध नहीं पहुंचने को भाग्य की संज्ञा देकर कहे कि जो भाग्य में था, वह प्राप्त हो गया। इसीलिए कटाक्ष के रूप में चालणी में दूध दुहे और भाग्य पर भरोसा करे की लोकोक्ति प्रचलन में आई है। बाजार भावों का चढ़ना-उतरना सरकारों की बेईमानी से ठासित भेदभावपूर्ण नीतियों का परिणाम है। फसल के दाम प्राप्ति की दिशा में बेईमानी को भाग्य समझने की भूल का सुधार ही एकमेव मार्ग है।

–रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

करौली शहर की कई कॉलोनियों में भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहराया

करौली, (निसं)। इन दिनों जैसे-जैसे गर्मी का दौर बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे ही शहर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जबकि शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल स्त्रोत होने के उपरांत जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी शहर में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं कर पा रहा है।

- **शहर की बिगड़ी पेयजल व्यवस्था को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी-कर्मचारी गंभीर नहीं है**

भीषण गर्मी के दौर में चौधरी की बगीची, सीताबाड़ी, भूडारा बाजार, गोमती कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, नूर कॉलोनी, लक्ष्मीकांत कॉलोनी, जाटव बस्ती, इंदिरा कॉलोनी सहित शहर की करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति के अभाव में पेयजल संकट गहरा रहा है। यही नहीं कई मोहल्ले में तो दो दिन में पानी मिल रहा है। इसके अलावा कई मोहल्ले में दूषित पानी मिल रहा है। इस भीषण गर्मी के दौर में दूषित पानी मिलाने से लोगों के पेट खराब हो रहे हैं और बीमारी फैलने की उम्मीद बढ़ रही है। शहर की बिगड़ी पेयजल व्यवस्था को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी गंभीर नहीं देखे जा रहे हैं। बिगड़ी पेयजल व्यवस्था का ठीकरा जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्युत निगम पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ने में पीछे नहीं है। जलदाय विभाग के अधिकारी-कर्मचारी यह कहते हैं कि बिजली नियमित रूप से नहीं मिलने के कारण टंकियों में पानी नहीं पहुंचता है, जिसके अभाव में पेयजल सप्लाई नियमित और पूरी नहीं हो पाती है।

राशिफल

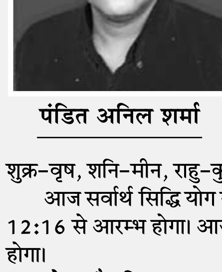

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 29 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, हस्त नक्षत्र रात्रि 12:16 तक, हर्षण योग रात्रि 8:51 तक, कौलव करण प्रातः 7:22 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 12:16 तक है। रवियोग रात्रि 12:16 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत है। अगस्त्य अस्त रात्रि 4:35 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:09 तक, शुभ 10:47 से 12:24 तक, चर 3:39 से 5:17 तक, लाभ 5:17 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:54, सूर्यास्त 6:54

मेष

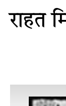

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। मन में बना हुआ भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

वृष

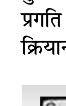

व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मिथुन

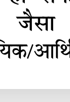

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

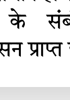

परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

सिंह

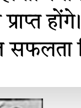

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला

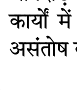

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृश्चिक

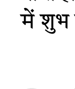

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

धनु

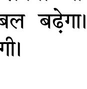

व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

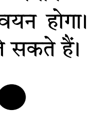

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कुंभ

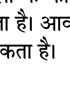

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। विवादित मामलों के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मीन

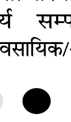

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।